राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

वर्ष – 04 | अंक – 10 | जौनपुर | शनिवार, 23 अगस्त 2025 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

सरकार विपक्ष की बात सुनेगी, लेकिन राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने जोर देकर कहा कि सरकार विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों को सुनेगी, लेकिन राष्ट्रीय हितों से कभी समझौता नहीं करेगी। किरेन रिजिजू शुक्रवार को नई दिल्ली के शंकर लाल ऑडिटोरियम में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। अपने आधिकारिक श्ग्श हैंडल पर एक पोस्ट साझा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने इस घटनाक्रम की जानकारी दी। श्ग्श पोस्ट में कहा गया कि सरकार विपक्ष की बात सुनेगी, लेकिन राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगी! हम 2047 तक विकसित भारत बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को पूरा करने के लिए समर्पित हैं! सभा को संबोधित करते हुए, किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार लोकतांत्रिक लोगों द्वारा चलाई जाती है और वे लोकतांत्रिक तरीके से काम करते हैं, यही वजह है कि उन्होंने संसद के पहले तीन हफ्तों में कोई विधेयक नहीं लाया। उन्होंने संसद में लगातार हो रहे हंगामे की ओर भी इशारा किया और कहा कि सरकार विपक्ष की बात सुनना चाहती है, लेकिन वे हमेशा हंगामा मचाते दिखते हैं। किरेन रिजिजू ने कहा कि हम देश की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। आपने (विपक्ष ने) विशेष गहन संशोधन के बारे में सुना होगा।

सुशासन के लिए न्याय को सुगम और त्वरित बनाना होगा : सीएम योगी

लखनऊ, (संवाददाता)। राजधानी लखनऊ में शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी न्यायिक सेवा संघ के 42वें सम्मेलन में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ ने 102 वर्षों के अपने इतिहास में अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को एक विकसित भारत के संकल्प के साथ जोड़ा है। सीएम ने कहा कि हम राज्य में कार्य कर रहे हैं, तो विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश बनेगा। हम जनपद में कार्य कर रहे हैं, तो विकसित उत्तर प्रदेश का विकसित जनपद बनेगा। यदि हमें सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें न्याय को सुगम

और त्वरित बनाना पड़ेगा।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ के 42वें सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यह अधिवशन ऐसे समय में आयोजित हो रहा है जब हमने भारत का संविधान लागू होने के अमृत महोत्सव वर्ष मे प्रवेश किया है और देशभर में भारत के संविधान के प्रति अपनी वचनबद्धता को लेकर आयोजन हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि न्याय समता और बंधुता भारत के संविधान की थीम है और ये सम्मेलन उसका प्रतीक है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने न्यायिक सेवा संघ के सम्मेलन में कहा कि किसी भी राज्य के लिए उसके परसेप्शन को जनमानस में विश्वास के रूप में प्रस्तुत करने के लिए, देश और दुनिया के सामने अपने आप को प्रस्तुत करने में न्यायपालिका की बड़ी भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि 'हम सब जानते हैं कि पीएम मोदी ने अमृत वर्ष पर विकसित भारत के संकल्प के साथ जोड़ा है। विकसित भारत की शुरुआत हमें अपनी ईकाई से प्रारंभ करना होगा। हम राज्य में कार्य कर रहे हैं तो विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश हैं। अगर हम जनपद में कार्य कर रहे हैं तो विकसित उत्तर प्रदेश का विकसित जनपद। हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन क्षेत्रों में समग्र विकास के साथ चलना होगा। ये सबकी खुशहाली का कारण बनेगा और उसका रास्ता प्रारंभ होता है एक सुदृढ़ न्याय व्यवस्था से। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि न्याय सुगम भी हो और और त्वरित भी हो। उन्होंने कहा कि 'अगर हमें सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करना हो तो न्याय को सुगम त्वरित भी बनाना पड़ेगा। इस दिशा में पिछले एक साल में जो प्रयास सराहनीय हैं। सालभर में हमारे जनपद और ट्रायल कोर्ट्स में बहत्तर लाख मामलों का निस्तारण हुआ हैं। लेकिन आज भी हमारे सामने चुनौती है कि एक करोड़ पंद्रह लाख से अधिक मामले लंबित पड़े हैं। जितने नए मामले आए थे ।

मध्य प्रदेश को मिलेगी करोड़ों की सौगात : मंत्री गड़करी

जबलपुर , (एजेंसी)। जबलपुर में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर बनकर तैयार हो गया है। आज शनिवार को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रदेश के सबसे बड़े और अत्याधुनिक फ्लाईओवर का लोकार्पण करेंगे। यह फ्लाईओवर जबलपुर शहर को नए यातायात स्वरूप में महानगरीय पहचान देगा। व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलेगी। जबलपुर एक नए यातायात मॉडल के रूप में देश के अन्य शहरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करेगा।आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीकों से निर्मित यह संरचना न केवल जबलपुर बल्कि पूरे देश के लिए एक अद्वितीय और प्रेरणादायी उदाहरण प्रस्तुत करती है।"

मुझे तूफानों से जूझने की आदत, आसुरी शक्ति से डरने वाली नहीं : रेखा गुप्ता

नई दिल्ली , (एजेंसी)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शनिवार को श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के वार्षिक दिवस समारोह में शामिल हुईं। इस दौरान सीएम ने जनसुनवाई के दौरान उनपर हुए हमले पर टिप्पणी की। सीएम ने अपने ऊपर हुए हमले पर बोलते हुए कहा कि मैं असुरी शक्तियों से डरने वाली नही हूं, मुझे तूफानों से जूझने की आदत है। उन्होंने कहा कि आज मेरे साथ दिल्लीवालों के प्यार और आशीर्वाद के रूप में बड़ी ताकत मौजूद है। वहीं, सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज एसआरसीसी के 99वें वार्षिकोत्सव पर परिसर में शिक्षकों और छात्रों से संवाद का अवसर मिला। सभी विजेताओं और प्रतिभागियों को ढेरों शुभकामनाएं। एसआरसीसी परिवार को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ। एशिया के

सर्वश्रेष्ठ कॉमर्स कॉलेज का यह गौरवशाली सफर हम सबके लिए गर्व का विषय है। कॉलेज जीवन की यादें सचमुच सुनहरी होती हैं। चाहे जीवन में हम कितनी भी ऊँचाइयाँ क्यों न छू लें, वे दिन हमेशा मन में ताजा रहते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा रही हूँ, इसलिए आज यह वातावरण मुझे अपने ही पुराने दिनों में लौटा ले गया। आज के युवाओं से अपील है कि अपने जीवन का एक हिस्सा राष्ट्र के उत्थान के लिए जरूर समर्पित करें। आइए, मिलकर एक नई, बेहतर और सशक्त दिल्ली बनाएं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर 20 अगस्त की सुबह हमला हुआ था। दिल्ली सीएम हाउस में यह घटना घटी। सीएम हाउस में मुख्यमंत्री रेखा साप्ताहिक जनसुनवाई कर रहीं थीं। इसी दौरान करीब 40 साल के एक शख्स ने हमला कर दिया।

गर्भस्थ शिशु की मौत मामले में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की कार्रवाई

लखनऊ, (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में इलाज के दौरान गर्भस्थ शिशु की मौत के मामले को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने गंभीरता से लिया है। निजी अस्पताल को सील कर दिया गया है। आशा बहू को नोटिस जारी किया गया है। महिला के निरूशुल्क इलाज के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। लखीमपुर खीरी के ग्राम नौसर जोगी निवासी विपिन गुप्ता की पत्नी रूबी को प्रसव पीड़ा होने पर बिजुआ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कराया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि अभी प्रसव का समय नहीं है। गर्भवती की तबीयत गड़बड़ है। लिहाजा गर्भवती को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। इसी दौरान विपिन की साली ने आशा बहू दीपा से संपर्क

किया।

रुपये जमा नहीं करने पर इलाज नहीं किया गया

आरोप है कि आशा बहू दीपा ने उसे महेवागंज के गोलदार हॉस्पिटल में भर्ती करावा दिया। वहां 21 अगस्त को चिकित्सक द्वारा गर्भवती को देखा गया। अस्पताल प्रबंधन ने रुपये जमा करने के लिए कहा। रुपये जमा नहीं करने पर गर्भवती महिला का इलाज नहीं किया गया। कुछ रुपए जमा करने के बाद इलाज शुरू किया गया। इलाज शुरू करते ही गर्भवती महिला की हालत ज्यादा गंभीर हो गई। आरोप है कि डॉक्टरों ने नर्सों की मदद से गर्भवती को अस्पताल से भगा दिया। इसके बाद परिजन गर्भवती रूबी को लेकर एक अन्य अस्पताल पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने जांच की बताया कि शिशु की पेट में मृत्यु हो चुकी है। गलत दवा खिलाने से ऐसा हुआ है। तब डॉक्टर द्वारा मृत बच्चा ऑपरेशन कर निकाला गया।

तीन सदस्यों की जांच कमेटी बनाई गई

परिजनों ने गोलदार अस्पताल प्रबंधन पर गलत इलाज का आरोप लगाया। मामले की जानकारी होने पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मुख्य चिकित्साधिकारी को अस्पताल सील करने का निर्देश दिया। ऐसे में तत्काल अस्पताल सील कर दिया गया है। आरोपी आशा को नोटिस जारी की गई है। तीन सदस्यों की जांच कमेटी बनाई गई है।

संसद भवन के गज द्वार पर खड़ा पेड़ सुरक्षा में बना बाधा, किया जाएगा स्थानांतरित

नई दिल्ली, (एजेंसी)। नए संसद भवन के छह प्रवेश द्वारों में से एक, गज द्वार पर स्थित एक चांदी के तुरही के पेड़ को विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) द्वारा सुरक्षा संबंधी चिंता के तौर पर चिह्नित किए जाने के बाद, परिसर के भीतर किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन में प्रवेश के लिए अक्सर इसी द्वार का उपयोग करते हैं। एसपीजी ने चिंता जताई थी कि यह पूर्ण विकसित पेड़, जिसे वृक्ष संख्या 01 कहा जाता है, वीवीआईपी मार्ग में संभावित बाधा उत्पन्न कर रहा है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) और दिल्ली वन विभाग सहित कई एजेंसियों ने इस मामले को उठाया, जिन्हें प्रत्यारोपण की मंजूरी देनी थी। एक अधिकारी के अनुसार सीपीडब्ल्यूडी द्वारा एसपीजी की सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए किए गए अनुरोध के बाद, दिल्ली वन विभाग द्वारा श्कड़ी शर्तोंश के अधीन अनुमति दिए जाने के साथ, संख्या 01 वाले पेड़ के प्रत्यारोपण की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। संसद के मानसून सत्र के समापन के बाद, पेड़ को स्थानांतरित करने का काम जल्द ही होने की संभावना है। इस वृक्ष के लिए चुना गया नया स्थल प्रेरणा स्थल है, जो संसद परिसर के भीतर स्थित है और जहाँ राष्ट्रीय नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियाँ स्थापित हैं।

भारत अपना स्पेस स्टेशन भी बनाएगा, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर अपने संबोधन में : पीएम मोदी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में भारत मंडपम में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान भारतीय अंतरिक्षयात्री शुभांशु शुक्ला के साथ गगनयान मिशन पर जाने वाले अन्य अंतरिक्षयात्री भी मौजूद रहे। साथ ही केंद्रीय विज्ञान और तकनीक मंत्री जितेंद्र सिंह और इसरो के चेयरमैन वी नारायणन भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने देशवासियों को दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार के अंतरिक्ष दिवस की थीम आर्यभट्ट से गगनयान तक

है। इसमें अतीत का आत्मविश्वास भी है और भविष्य का संकल्प भी। आज हम देख रहे हैं कि इतने कम समय में ही राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हमारे युवाओं के बीच उत्साह और आकर्षण का विषय बन गया है। यह देश के लिए गौरव की बात है।श्र प्रधानमंत्री ने कहा कि श्अंतरिक्ष क्षेत्र में एक के बाद एक नई उपलब्धि हासिल करना, ये भारत और भारत के वैज्ञानिकों का स्वभाव बन गया है। दो साल पहले ही भारत ऐसा पहला देश बना था जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने का इतिहास रचा। हम उन देशों में भी शामिल हो गए हैं, जिन्होंने अंतरिक्ष में डॉकिंग और अनडॉकिंग की क्षमता हासिल कर ली है। उन्होंने कहा कि शुभांशु शुक्ला ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर तिरंगा फहराकर हर भारतीय को गर्व से भर दिया। जब वो तिरंगा मुझे दिखा रहे थे, जो वो पल और अनुभूति थी। वो शब्दों से परे हैं। आज भारत सेमी क्रायोजेनिक इंजन और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन जैसी अहम तकनीक की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जल्द ही अपने वैज्ञानिकों की मेहनत से गगनयान भी सफलता की उड़ान भरेगा और आने वाले समय में भारत अपना स्पेस स्टेशन भी बनाएगा।

बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर मुकदमा दर्ज

ललितपुर, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने पर बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री राजद नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ तालबेहट कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मुकदमा भाजपा जिलाध्यक्ष हरिश्चंद्र रावत ने दर्ज कराया है। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हरिश्चंद्र रावत ने पुलिस को तहरीर दी। जिसमे बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से ज्ञात हुआ कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ तेजस्वी यादव एवं अन्य लोगों ने अभद्र टिप्पणी की है। पुलिस ने तेजस्वी यादव व अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मालूम हो कि राजद के एक्स हैंडल से आपत्तिजनक पोस्ट किया गया था। पोस्ट में प्रधानमंत्री की तस्वीर भी लगाई गई थी। शिकायतकर्ता ने पोस्ट की कॉपी को मुकदमे में सबूत के तौर पर पेश किया है। तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद स्थानीय स्तर पर राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है।

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर जेलों में बंद दंडित बंदियों को सजा में मिलेगी करीब 60 दिन की छूट : मोहन यादव

मुबई, (एजेंसी)। मध्य प्रदेश में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया जायेगा, सरकार ने भी इसके लिए आदेश दिए है, कृष्ण

मंदिरों में आकर्षक सजावट की जाएगी, श्री कृष्ण प्रदेशवासियों के लिए खुशियाँ लेकर आएंगे, इसके साथ ही श्रीकृष्ण बंदियों के जीवन में भी खुशियाँ लेकर आये हैं, सरकार ने तय किया है कि दंडित बंदियों को उनकी सजा में करीब 60 दिन की छूट दी जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने जेलों में अपने अपराध की सजा भुगत रहे बंदियों को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर बड़ी राहत दी है, मुख्यमंत्री ने बंदियों की सजा मने 60 दिन की छूट देने की घोषणा की है, उन्होंने जेल विभाग को इस आशय के निर्देश जारी किये हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सरकार के इस फैसले की जानकारी ग पर देते हुए लिखा कि श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर इस वर्ष भी प्रदेश की जेलों के दंडित बंदियों को सजा में करीब 60 दिन की छूट हेतु जेल विभाग को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि जिन बंदियों को सजा में 60 दिन की छूट का लाभ मिलेगा उनमें आतंकवादी गतिविधि, लैंगिक अपराध, हत्या के गंभीर आरोपी शामिल नहीं हैं। मुख्यमंत्री के मुताबिक मध्य प्रदेश के जेलों में बंद 21 हजार बंदियों में से लगभग 14 हजार बंदी इससे लाभान्वित होंगे।

सीपी राधाकृष्णन-सुदर्शन रेड्डी के अलावा 46 उम्मीदवारों ने किया था नामांकन

नई दिल्ली, (एजेंसी)। उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को होने वाले चुनाव की तस्वीर अब पूरी तरह से साफ हो गई है। नामांकन प्रक्रिया और जांच की सभी औपचारिकताओं के बाद अब केवल दो उम्मीदवार ही चुनावी मैदान में बचे हैं। सत्तारूढ़ राजग उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी के बीच अब सीधा मुकाबला होने वाला है। इसे दक्षिण बनाम दक्षिण की लड़ाई बताया जा रहा है, क्योंकि दोनों ही दक्षिण भारत से आते हैं। निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने बताया है कि दोनों उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों के सभी चार सेट सही पाए गए हैं। राधाकृष्णन

तमिलनाडु से भाजपा के वरिष्ठ नेता और वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, जबकि तेलंगाना से आने वाले रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं।

46 उम्मीदवारों ने 68 नामांकन पत्र दाखिल किए

इस बार उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर उम्मीदवारों में काफी उत्साह देखने को मिला है। कुल 46 उम्मीदवारों ने 68 नामांकन पत्र दाखिल किए, लेकिन इनमें से बड़ी संख्या प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज कर दिए गए। दरअसल, 19 उम्मीदवारों के 28 नामांकन पत्र तकनीकी आधार पर स्वीकार नहीं किए गए। वहीं, 27 उम्मीदवारों के 40 नामांकन पत्रों की जांच 22 अगस्त को की गई। इस दौरान चुनाव से जुड़े नियमों के तहत कई नामांकन पत्र अमान्य करार दे दिए गए। नतीजतन अंत में केवल दो उम्मीदवारों के नामांकन पत्र वैध पाए गए। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी और महासचिव राज्य सभा का कार्यालय के तरफ दी गई जानकारी के अनुसार, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के साथ ही 7 अगस्त 2025 से ही प्रक्रिया आरंभ हो गई थी। नाम निर्देशन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त 2025 निर्धारित की गई थी, जबकि नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि 22 अगस्त, 2025 निर्धारित की गई थी। 7 से 21 अगस्त 2025 की अवधि के दौरान उपराष्ट्रपती निर्वाचन 2025 के लिए निर्वाचन अधिकारी और राज्य सभा के महासचिव को 46 अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल कुल 68 नामनिर्देशन पत्र प्राप्त हुए। इन 68 नामनिर्देशन पत्रों में से 19 अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल किए गए 28 नामनिर्देशन पत्रों को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 5 ख(4) के अनुसार अस्वीकृत कर दिया गया था। 27 अभ्यर्थियों के 40 नाम निर्देशन पत्रों की 22 अगस्त, 2025 को मध्याह्न पूर्व 11 बजे संवीक्षा की गई। संवीक्षा के दौरान राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 5 ख(1)(ख) या 5 ख(1)(ख) और 5ग के उपबंधों के अधीन नामनिर्देशन पत्रों को अस्वीकृत कर दिया गया।

संपादकीय

महामारी मोटापे की

देश में जिस तेजी से मोटापा और उससे जनित रोगों का दायरा बढ़ा है, उससे यह एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात जैसी स्थिति बनती जा रही है। जिससे मोटापा जनित गैर संक्रामक रोगों में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। एक हालिया अध्ययन में इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च व विश्व स्वास्थ्य संगठन ने खुलासा किया है कि साल 2025 तक भारत की वयस्क आबादी में मोटापे की दर 20 से 23 फीसदी तक जा पहुंची है। जबकि वर्ष 1990 में देश यह दर महज नौ से दस प्रतिशत ही थी। चिंता की बात यह है कि महज तीन दशक में मोटापा बढ़ने की यह दर दो गुना हो चुकी है। यही वजह है कि शहरों में आजकल हर चौथा व्यक्ति मोटापे का शिकार दिखायी देता है। दरअसल, देश में जैसे–जैसे आर्थिक समृद्धि आई तो हमारी खान–पान की आदतों में बदलाव आया है। हमारे भोजन में डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ, अधिक शूगर वाले पेय पदार्थ और युवाओं में जंक फूड का उपभोग तेजी से बढ़ा है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि खाद्य तेलों का उपयोग भी बहुत तेज गति से बढ़ा है। आर्थिक विकास से समृद्धि आई तो हमारा खानपान समृद्ध हुआ,लेकिन वहीं शारीरिक निष्क्रियता भी बढ़ी है। दरअसल, खाद्य तेलों का बेतहाशा उपयोग भी मोटापे की वजह बना है। देश में नब्बे के दशक में जहां प्रति व्यक्ति तेल की औसतन खपत साढ़े तीन से चार लीटर थी, जो अब करीब बीस लीटर सालाना हो गई है। यानी चिंताजनक स्थिति तक पहुंचकर पांच गुना हो गई है। अब मोटापे की समस्या से शहर ही नहीं, ग्रामीण जीवन भी प्रभावित हो रहा है। बीती सदी में ऐसा देखने में नहीं आता है। दरअसल, इस सदी की शुरुआत में आई आर्थिक समृद्धि ने न केवल हमारी खानपान की आदतें बदली, बल्कि वाहनों के अधिक उपयोग व आरामदायक जीवनशैली ने हमारी शारीरिक सक्रियता भी कम कर दी। जो मोटापे की एक बड़ी वजह बना। देश में मोटापे की समस्या किस हद तक पहुंच चुकी है और उससे गैर संक्रामक रोग कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, उसको लेकर कई सार्वजनिक मंचों से प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर चुके हैं। स्वतंत्रता दिवस पर उन्होंने देश में गति पकड़ते मोटापे पर गंभीर चिंता जतायी। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर भी वे मोटापे से मुक्त जीवन के लिये लाइफ स्टाइल में बदलाव की बात कह चुके हैं। उन्होंने खाद्य तेलों के उपयोग में कमी लाने की भी बात कही। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कह चुका है कि पांच–छह सौ एमएल से अधिक खाद्य तेल का सेवन मोटापे, उच्च रक्तचाप, दिल के रोग और डायबिटीज के खतरे को बढ़ा सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कह रहे हैं कि खानपान की आदतों में सुधार और शारीरिक सक्रियता बढ़ाने से हम मोटापा कम कर सकते हैं। नियमित व्यायाम व योग–प्राणायाम इसमें खासे मददगार हैं। यहां संकट हमारी जीवन शैली में आये बदलावों का भी है, जिसमें हम देर रात को अधिक गरिष्ठ भोजन करते हैं। देर से सोना और देर से जागना अब आम बात हो चली है। तेजी से होते शहरीकरण, आफिसों में देर तक काम करने, शारीरिक सक्रियता में कमी तथा देर रात तक सोशल मीडिया में उलझे रहने से भी नींद की कमी ने जीवन में तनाव को बढ़ाया है। यह तनाव हमारी खानपान की आदतों को बुरी तरह प्रभावित करके मोटापे को बढ़ाता है। यही वजह है कि एक बहुचर्चित मेडिकल पत्रिका ने चेताया है।

मानसून के लिए नई रणनीति बनाने की जरूरत

दीपक

जलवायु परिवर्तन ने मानसून के पैटर्न में बदलाव किया है और भारी बारिश की घटनाओं को बढ़ाया है, भारत की नीतियों, योजनाओं और डेटा प्रणालियों को इसके साथ तालमेल बनाना चाहिए। लचीलापन विकसित करने का अर्थ है कि आसमान अभी हमें जो बता रहा है, उसके अनुरूप खुद को ढालना है, न कि पहले से क्या करते आ रहे

थे, उसे दोहराना। दक्षिण–पश्चिम मानसून को भारत की जल और खाद्य तंत्र की रीढ़ कहा जाता है, जो जून से सितंबर के बीच देश में लगभग तीन–चौथाई वार्षिक वर्षा लाता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने इस साल सामान्य से अधिक मानसून का अनुमान लगाया है। लेकिन इसमें सिर्फ यही मायने नहीं रखता है कि कुल कितनी बारिश हुई, बल्कि यह भी अहम है कि कब, कहां और कैसी बारिश हुई है। जलवायु परिवर्तन ने बारिश के पैटर्न को अनियमित बनाया है। वर्ष 2025 में अब तक का मानसून पूरे देश में भारी और कम वर्षा की विरोधी घटनाओं से भरा हुआ है। जुलाई में अच्छी बारिश ने खरीफ की बुवाई को तेज कर दिया, माह के अंत तक 70.8 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बुवाई हुई, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि से 4.1 प्रतिशत अधिक रही। दूसरी तरफ केरल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों को अत्यधिक बारिश से जूझना पड़ा है, जिससे अचानक बाढ़ की घटनाएं सामने आई हैं। सीईईडब्ल्यू के एक अध्ययन में पाया गया कि 55 प्रतिशत तहसीलों में जून से सितंबर के बीच कुल बारिश बढ़ी है। खास बात यह कि यह बढ़ोतरी भारी बारिश वाले दिनों की संख्या बढ़ने से हुई है। नेचर में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार पिछले चार दशकों में प्रति घंटे बारिश के पैटर्न की पड़ताल में सामने आया है कि मध्य भारत में कम समय में भारी बारिश और उत्तर–पश्चिमी तट पर लंबे समय तक भारी बारिश की घटनाएं अधिक संख्या में हो रही हैं। पिछले दो दशकों में भारत सरकार और राज्य सरकारों ने मौसम पूर्वानुमान प्रणालियों में उल्लेखनीय रूप से निवेश किया है और देश व राज्यों के स्तर पर जलवायु कार्य योजनाएं शुरू की हैं। जिस तरह से जलवायु परिवर्तन बढ़ रहा है, और बारिश में तेजी से अनियमितता आ रही है, इसका सामना करने की क्षमता विकसित करने में ये तीन कदम सहायक हो सकते हैं। पहला, शहरों को बीते कल के औसत के लिए नहीं, बल्कि आज के तूफानों के लिए योजना बनानी चाहिए। शहरी स्थानीय निकायों को बाढ़ का सामना करने के लिए बनाई जाने वाली योजना का दोबारा मूल्यांकन करना चाहिए। पारंपरिक बाढ़ प्रबंधन इस ऐतिहासिक डेटा पर निर्भर करता है कि कितनी बार और कितनी भारी बारिश हुई है, जिसे तूफानी घटनाओं की तीव्रता–अवधि–आवृत्ति कहा जाता है। लेकिन अब यह विश्वसनीय नहीं रह गया है, क्योंकि तापमान बढ़ने के साथ हवा में नमी की मात्रा बढ़ जाती है, जिसका मतलब लंबे समय तक सूखा पड़ना और फिर बहुत तेज बारिश होना है। महाराष्ट्र के ठाणे में पुराने जल–निकासी तंत्र (ड्रेनेज सिस्टम) को एक घंटे की अधिकतम बारिश को संभालने के लिए नहीं बनाया गया था, जबकि बीते एक दशक में औसतन बारिश 64 मिमी प्रति घंटा रही है। (संदर्भ के लिए, 100 मिमी प्रति घंटा बारिश को बादल फटना माना जाता है।) इसे समझते हुए, ठाणे नगर निगम ने अपने बाढ़ के खतरे के अनुमानों में बदलाव किया है और अब अपने तूफानी जल–निकासी वाले नालों (स्टॉर्म वॉटर ड्रेन्स) को फिर से बना रहा है। भारत के अन्य शहरों को भी ऐसा करना चाहिए। दूसरा, किसानों को अपने फसल कैलेंडर को अपडेट करने की जरूरत है। बारिश के बदलते पैटर्न के साथ, राज्यों और केंद्रीय कृषि विभागों और मौसम विज्ञान एजेंसियों को मिलकर फसल कैलेंडर को अपडेट करना चाहिए, खास तौर पर जिन क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती होती है। अध्ययन से पता चलता है कि अनिश्चित मानसूनी बारिश विशेष रूप से धान, मक्का और दालों जैसी प्रमुख फसलों के बुवाई और कटाई के मौसम को बदल रही है। वहीं, भारत की आधी से अधिक तहसीलों में अक्तूबर महीने में बारिश में वृद्धि देखी गई, जिससे फसलों की कटाई प्रभावित होती है। परंपरागत रूप से फसल का नुकसान होने पर राहत भुगतान की शुरुआत हो जाती है। लेकिन एक अधिक दूरदर्शी दृष्टिकोण में फसल चक्रों को नए सिरे से व्यवस्थित करना, जलवायु–अनुकूल बीज उपलब्ध कराना, और किसानों की सुरक्षा के लिए आकस्मिक योजनाओं का निर्माण शामिल होना चाहिए। तीन, स्थानीय स्तर पर मौसम के अधिक सूक्ष्म आंकड़ों को जुटाने में निवेश करें और उनके उपयोग की क्षमता बढ़ाएं।

कसौटी पर हरियाणा सामुदायिक सेवा दंड दिशा–निर्देश

गोपाल

हरियाणा सरकार द्वारा अधिसूचित हालिया सामुदायिक सेवा दिशा–निर्देश भारतीय न्याय संहिता की धारा 4 (एफ) और संविधान के अनु. 162 के तहत निर्मित बताये गये हैं। लेकिन उक्त केंद्रीय कानूनों में राज्यों को सामुदायिक सेवा दंड संबंधी नियम बनाने की शक्ति प्रदान करने वाला प्रावधान नहीं। उक्त दस्तावेज की कानूनी वैधता पर सवाल स्वाभाविक है। दिल्ली के बाद, हरियाणा सरकार ने भी 16 अगस्त, 2025 को सामुदायिक सेवा दिशा–निर्देश (एचसीएसजी) अधिसूचित कर दिए हैं। दोनों ही दिशा–निर्देशों के आरम्भिक वाक्य में कहा गया है कि ये दिशा–निर्देश भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस) की धारा 4 (एफ) और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के अंतर्गत बनाए गए हैं, जबकि इनमें से कोई भी प्रावधान राज्य सरकार को ऐसे दिशा–निर्देश जारी करने का अधिकार नहीं देता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 4 (एफ) अपराधियों को दी जाने वाली सजा के प्रकार उल्लिखित करती है, तथा संविधान के अनुच्छेद 162 में राज्यों की कार्यकारी शक्तियों की सीमा का प्रावधान है। किसी भी विषय पर नियम अथवा दिशा–निर्देश जारी करने की शक्तियां सम्बन्धित कानून में स्पष्ट रूप से लिखित प्रावधान द्वारा कार्यपालिका को प्रदान की जाती हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) और भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस) दोनों ही केन्द्रीय कानून हैं और राज्य सरकारें सामुदायिक सेवा दंड (सीएसएस) के निष्पादन पर प्रत्यायोजित (डेलिगेटिड) कानून का सहारा उसी परिस्थिति में ले सकती हैं जब इन कानूनों में इसका स्पष्ट प्रावधान हो। हरियाणा सामुदायिक सेवा दंड दिशा–निर्देशों को जायज ठहराने के लिए राज्यों को इससे संबंधित नियम बनाने की शक्ति प्रदान करने वाला कोई प्रावधान नहीं है, जिससे पूरी प्रक्रिया बिना कानूनी आधार की गतिविधि मात्र बनकर रह जाती है। वास्तव में, बीएनएसएस का मसौदा तैयार करते समय विधान मंडल अनभिज्ञता से अध्याय 34 में सीएसएस के निष्पादन से सम्बन्धित उचित प्रावधान जोड़ना भूल गए, जैसा कि पहले से ही मृत्यु दंड, कारावास अथवा जुर्माना लगाने की सजा के निष्पादन के लिए किया गया है।

यह त्रुटि शायद लापरवाही के कारण हुई क्योंकि सामुदायिक सेवा को बीएनएस में पहली बार दंड की सूची में शामिल किया गया था। परिणामस्वरूप, सीएसएस के निष्पादन पर नियम बनाने की शक्ति भी गैर–निर्देशित रह गई। आदर्श रूप से, हरियाणा सामुदायिक सेवा दंड दिशा–निर्देश तैयार करने से पूर्व, राज्य सरकार को केन्द्र सरकार के समक्ष बीएनएसएस में वर्णित द्वारा 460 के बाद एक नए उप–शीर्षक 'सामुदायिक सेवा' के अन्तर्गत एक नई धारा शामिल करने का प्रस्ताव भेजना चाहिए था। ऐसे प्रत्यायोजित शक्तियों के अभाव में, हरियाणा सामुदायिक सेवा दंड दिशा–निर्देश और दिल्ली के दिशा–निर्देश, राज्य–कार्यपालिका की विधायी अक्षमता का शिकार हैं और दोनों ही दस्तावेज गैर–कानूनी हैं। यह आश्चर्यजनक है कि दिशा–निर्देशों को अधिसूचित करने से पहले इतनी बड़ी गलती कैसे उजागर नहीं हो सकी। हरियाणा सामुदायिक सेवा दंड दिशा–निर्देश कई अन्य प्रकार से भी संदिग्ध प्रतीत होते हैं। सबसे पहले, दिशा–निर्देश यह वर्णित करते हैं कि वे उन मामलों पर भी लागू होंगे जहां बाल–न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 (जेजे एक्ट) की धारा 18(1) (सी) के अन्तर्गत बच्चों को सामुदायिक सेवा करने के आदेश पारित किए जाते हैं। चूंकि बाल–अधिनियम महिला और बाल विकास विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए यह उचित नहीं है कि गृह विभाग इसके कार्यान्वयन पर दिशा–निर्देश जारी करे। दूसरा, उक्त दिशा–निर्देशों के पैरा 7 में अदालतों के लिए एक सुझाव दिया गया है कि सीएसएस आमतौर पर पहली बार अपराध करने वालों को दिया जाना चाहिए, जबकि बीएनएस में, छोटी–मोटी चोरी के मामलों को छोड़कर, ऐसी कोई शर्त नहीं रखी गई है। इससे यह प्रासांगिक प्रश्न भी उठता है कि 'क्या कार्यपालिका दिशा–निर्देशों में ऐसी कोई अतिरिक्त शर्तें निर्धारित कर सकती है ।

..... विविध .....

पढ़ा-लिखा बच्चा अगर जल्दी भूल जाता है तो उसे खिलाएं ये आयुर्वेदिक पाउडर

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में सिर्फ बड़े ही नहीं बल्कि बच्चे भी तनाव और दबाव का सामना करते हैं। कम उम्र से ही बच्चों पर पढ़ाई का बोझ इतना बढ़ जाता है कि उनका दिमाग थकने लगता है। नतीजा यह होता है कि वे पढ़ा हुआ जल्दी भूल जाते हैं, ध्यान (विबने) लगाने में दिक्कत होती है और कभी–कभी तो पढ़ाई में बिल्कुल मन भी नहीं लगता। वहीं, उम्र बढ़ने के साथ बड़ों में भी भूलने की समस्या आम हो जाती है। इन्हीं समस्याओं से निपटने के लिए न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने एक खास आयुर्वेदिक ब्रेन बूस्टिंग पाउडर बनाने की सलाह दी है। यह पाउडर न सिर्फ बच्चों के दिमाग को तेज करेगा बल्कि बड़े–बुजुर्गों की याददाश्त भी मजबूत बनाएगा।

ब्रेन बूस्टिंग पाउडर बनाने के लिए सामग्री

शंखपुष्पी पाउडर – 2 चम्मच
वाछा पाउडर – 1 चम्मच
मुलेठी पाउडर – 1 चम्मच
सोंठ पाउडर – 1 चम्मच
बादाम पाउडर – 2 चम्मच
पंपकिन सीड्स (कद्दू के बीज)
इलायची पाउडर
मगज (खरबूजे के बीज)

बनाने का तरीका – इन सभी चीजों को हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लें। ठंडा होने के बाद इन्हें पीसकर बारीक पाउडर बना लें और एयर टाइट डिब्बे में भरकर रख दें।

खाने का तरीका

इस पाउडर को खाने का तरीका बहुत आसान है। रोजाना सुबह नाश्ते के बाद और शाम को खाने के बाद एक–एक चम्मच पाउडर लेना चाहिए। नियमित रूप से इसका सेवन करने से दिमाग को जरूरी पोषण मिलता है, याददाश्त मजबूत होती है और फोकस बढ़ाने में मदद मिलती है।

पाउडर में मिलाए गए हर्ब्स और बीजों के फायदे

इस ब्रेन बूस्टिंग पाउडर में डाले गए आयुर्वेदिक हर्ब्स और बीज दिमाग के लिए बेहद फायदेमंद साबित होते हैं। इनमें मौजूद ब्राह्मी पाउडर माइंड को फोकस करने में मदद करता है, वहीं शंखपुष्पी याददाश्त को मजबूत बनाती है। वाछा पाउडर बोलने की शक्ति को बढ़ाकर स्पीच को क्लियर करता है। मुलेठी का हल्का मीठा स्वाद इसे खाने में आसान बनाता है और साथ ही यह बढ़ती उम्र में दिमाग के काम करने की क्षमता को संतुलित रखता है। दिमाग को शार्प बनाने के लिए इसमें सोंठ भी मिलाई जाती है, जो पाचन को दुरुस्त रखती है ताकि शरीर सभी पोषक तत्वों को अच्छे से अवशोषित कर सके। बादाम इसमें विटामिन ई और गुड फैट्स का स्रोत है, जो दिमाग को पोषण देकर तेज बनाते हैं। पंपकिन सीड्स मैग्नीशियम और जिंक से भरपूर होते हैं, जो ब्रेन पावर और मेमोरी को बढ़ाते हैं। इलायची दिमाग को साफ और शांत रखती है, जिससे सोचने–समझने की क्षमता बेहतर होती है। वहीं खरबूजे के बीज यानी मगज शरीर को ठंडक देते हैं और ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शन को मजबूत करते हैं।

किसे होगा फायदा?

यह आयुर्वेदिक पाउडर हर उम्र के लोगों के लिए फायदेमंद है। बच्चों को इसका सेवन करने से पढ़ाई में ध्यान लगाने और सीखी हुई चीजें लंबे समय तक याद रखने में मदद मिलती है। युवाओं के लिए यह पाउडर ऑफिस वर्क या पढ़ाई के दौरान लंबे समय तक फोकस बनाए रखने में सहायक है। वहीं बुजुर्गों के लिए यह दिमाग को एक्टिव रखता है और उम्र बढ़ने के साथ होने वाली भूलने की समस्या को कम करने में मदद करता है। सबसे खास बात यह है कि यह पाउडर पूरी तरह प्राकृतिक है और लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर भी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता।

शाकाहारी हैं तो घबराएं नहीं बिना नॉनवेज खाए ऐसे बढ़ाएं विटामिन बी122

शरीर में सभी विटामिन और मिनरल्स का सही स्तर होना जरूरी है। लेकिन आजकल विटामिन बी12 की कमी बहुत आम हो गई है। यह विटामिन खासतौर पर नॉन वेज खाने में ज्यादा पाया जाता है, इसलिए जो लोग शाकाहारी हैं या नॉन वेज नहीं खाते, उन्हें इसकी कमी हो सकती है। चलिए जानते हैं कि बिना नॉन वेज लिए भी कैसे विटामिन बी12 का स्तर बढ़ाया जा सकता है।

शाकाहारी लोगों में विटामिन बी12 की कमी

शाकाहारी भोजन में विटामिन बी12 बहुत कम होता है, इसलिए शाकाहारी लोगों में इसकी कमी सबसे ज्यादा देखी जाती है। इस कमी के कारण शरीर कमजोर महसूस हो सकता है, हाथ–पैर सुन्न हो सकते हैं और नसों को नुकसान भी हो सकता है। इसलिए शरीर में विटामिन बी12 का सही स्तर बनाए रखना जरूरी होता है।

विटामिन बी12 कमी के लक्षण

विटामिन बी12 की कमी शरीर में कई तरह के लक्षणों के रूप में सामने आती है, जिन्हें नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। इसकी कमी के सबसे सामान्य संकेतों में लगातार थकान महसूस होना, मतली या जी मिचलाना, बिना कोशिश के वजन कम होना और त्वचा का पीला पड़ना शामिल है। इसके अलावा जीभ में सूजन आना, हाथ–पैरों में झनझनाहट या सुन्नता महसूस होना, नजर धुंधली होना और याददाश्त कमजोर पड़ना भी इसके संकेत हो सकते हैं। कुछ लोगों को बोलने या चलने में भी परेशानी होने लगती है। मानसिक लक्षणों में चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन की समस्या भी देखी जा सकती है। यदि आपको इनमें से कोई भी लक्षण महसूस हो, तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें और आवश्यक जांच करवाएं।

विटामिन बी12 की कमी क्यों होती है?

बी12 की कमी के कई कारण हो सकते हैं, जैसे खाने में विटामिन बी12 का कम होना, पेट में सूजन या गैस्ट्रिक इंफ्लामेशन। पर्निशियस एनीमिया (रक्त की बीमारी), पाचन तंत्र की समस्याएं किसी सर्जरी के बाद पाचन क्षमता का कम होना।अधिक शराब का सेवन, ट्रांसकोबालामिन 2 की कमी, इन कारणों से शरीर में बी12 का स्तर कम हो सकता है।

विटामिन बी12 बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका

डॉक्टरों के अनुसार विटामिन बी12 की कमी का इलाज नेजल जेल या नेजल स्प्रे से किया जा सकता है, जो बहुत असरदार होते हैं। इसके अलावा ओरल मेडिकेशन (गोली) और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन भी लिए जा सकते हैं। यह तरीके शरीर में बी12 का स्तर जल्दी और प्रभावी रूप से बढ़ाते हैं।

जल्दी ऑफिस जाने की वजह से स्किप कर देते ब्रेकफास्ट, तो जान लें इसके नुकसान

सुबह का नाश्ता यानी ब्रेकफास्ट हमारे दिन का पहला और सबसे जरूरी भोजन होता है। लेकिन अक्सर लोग समय की कमी, देर तक सोने की आदत या जल्दी ऑफिस जाने की वजह से इसे स्किप कर देते हैं। कई लोगों का मानना है कि ब्रेकफास्ट न करने से शरीर को कोई खास नुकसान नहीं होता और लंच में भरपेट खाकर इसकी कमी पूरी हो सकती है। लेकिन सच यह है कि सुबह का नाश्ता छोड़ना सेहत के लिए बेहद हानिकारक है। आइए जानते हैं कि ब्रेकफास्ट न करने से शरीर को कौन–कौन से नुकसान हो सकते हैं।

वजन बढ़ना

ब्रेकफास्ट आपके शरीर को रातभर की फास्टिंग के बाद नई शुरुआत देता है। जब आप सुबह का नाश्ता नहीं करते, तो शरीर को तुरंत एनर्जी की तलाश रहती है और इस वजह से दिन में मीठा, तैलीय और हाई–कैलोरी वाला खाना खाने की क्रेविंग बढ़ जाती है। ऐसे फूड्स का सेवन धीरे–धीरे आपके वजन को घटाने की बजाय बढ़ाने लगता है। साथ ही, ज्यादा भूख लगने पर अक्सर हम जरूरत से ज़्यादा खा लेते हैं, जिससे अनहेल्दी फैट शरीर में जमा हो जाता है। इसलिए ब्रेकफास्ट छोड़ना वजन कंट्रोल करने का उपाय नहीं बल्कि वजन बढ़ाने का एक बड़ा कारण है।

एनर्जी की कमी और थकान

जब हम रातभर सोते हैं तो हमारा शरीर कई घंटों तक बिना खाए रहता है। ऐसे में सुबह का नाश्ता शरीर को नई ऊर्जा देने का काम करता है और दिन की शुरुआत को सक्रिय बनाता है। लेकिन अगर आप ब्रेकफास्ट छोड़ देते हैं, तो शरीर को जरूरी फ्यूल नहीं मिल पाता। इस वजह से पूरे दिन सुस्ती, थकान और कमजोरी बनी रहती है। नाश्ता न करने वालों को अक्सर काम करते समय जल्दी थकान महसूस होती है और उनका ध्यान भी बार–बार भटकता है। इसका सीधा असर प्रोडक्टिविटी और मूड पर पड़ता है। यानी, ब्रेकफास्ट स्किप करने से न केवल आपकी सेहत प्रभावित होती है बल्कि आपके काम करने की क्षमता भी घट जाती है।

चिड़चिड़ापन और मूड स्विंग्स

सुबह का नाश्ता करने से शरीर

को ग्लूकोज मिलता है, जो ब्लड शुगर लेवल को संतुलित रखता है। लेकिन जब आप नाश्ता छोड़ देते हैं तो ब्लड शुगर लेवल गिर जाता है। इससे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन (जैसे कोर्टिसोल) की मात्रा बढ़ने लगती है। नतीजा आप जल्दी गुस्सा करने लगते हैं, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है और मूड भी बार–बार बदलने लगता है। लंबे समय तक यह आदत आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकती है। यानी, सुबह का नाश्ता केवल शरीर को ऊर्जा नहीं देता बल्कि आपके मूड और मानसिक स्थिरता के लिए भी जरूरी है।

पोषक तत्वों की कमी

ब्रेकफास्ट दिनभर के लिए जरूरी पोषक तत्वों का एक बड़ा स्रोत होता है। इसमें विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन और फाइबर जैसे न्यूट्रिएंट्स शामिल होते हैं, जो शरीर को मजबूत और स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। लेकिन जब आप नाश्ता नहीं करते, तो शरीर को ये जरूरी तत्व समय पर नहीं मिल पाते। धीरे–धीरे यह कमी डिफिशिएंसी डिजीज यानी पोषण की कमी से होने वाली बीमारियों का कारण बन सकती है। इसके अलावा, नाश्ता स्किप करने से इम्यून सिस्टम भी कमजोर हो जाता है और शरीर जल्दी–जल्दी बीमार पड़ने लगता है।

दिल की बीमारियों का खतरा

कई रिसर्च में यह पाया गया है कि जो लोग नियमित रूप से नाश्ता नहीं करते, उनमें मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज का खतरा अधिक रहता है। ये सभी समस्याएं आगे चलकर हार्ट डिजीज का कारण बनती हैं। यानी, सुबह का नाश्ता स्किप करना आपके दिल की सेहत पर सीधा असर डालता है। यहां तक कि नाश्ता देर से करने की आदत भी हार्ट के लिए नुकसानदेह मानी जाती है। इसलिए अगर आप अपने दिल को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो ब्रेकफास्ट को कभी भी नजरअंदाज न करें।

सुबह का नाश्ता छोड़ना शरीर के लिए किसी भी तरह से फायदेमंद नहीं है। यह आपके वजन, एनर्जी लेवल, मूड, पोषण और दिल की सेहत सभी को प्रभावित करता है। इसलिए चाहे आप कितने भी व्यस्त क्यों न हों, सुबह का हल्का लेकिन पौष्टिक नाश्ता जरूर करें। ब्रेकफास्ट को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाकर आप लंबे समय तक फिट, एनर्जेटिक और हेल्दी रह सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आवारा कुत्तों के लिए शहर में बनेंगे आहार स्थल

लखनऊ, (संवाददाता)। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब आवारा कुत्तों के लिए आवासीय समितियों के सहयोग से आहार स्थल (फीडिंग सेंटर) बनाए जाएंगे। लोग इन्हीं आहार स्थल पर कुत्तों को भोजन करा सकेंगे। इस प्रकार के फीडिंग सेंटर आबादी से थोड़ी दूरी पर खाली और एकांत जगहों पर बनाए जाएंगे। शहर में इस समय अनुमानित करीब 1.20 लाख आवारा कुत्ते हैं। नगर निगम की ओर से एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) नियमों के तहत करीब 96 हजार आवारा कुत्तों की नसबंदी की जा चुकी है। पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अभिनव वर्मा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत सिर्फ काटने वाले कुत्तों को ही पकड़ कर सेंटर में रखा जाएगा।

नगर निगम कार्यकारिणी बैठक में हंगामा, पार्षदों ने अफसरों को घेरा

लखनऊ, (संवाददाता)। नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक शुक्रवार को हंगामे और आरोप–प्रतिवाद के बीच बिना नतीजे के समाप्त हो गई। सुबह 11 बजे शुरू हुई बैठक दोपहर दो बजे तक चली, लेकिन एजेंडे के किसी प्रस्ताव पर चर्चा तक नहीं हो सकी। कार्यकारिणी सदस्य अफसरों के जवाबों से संतुष्ट नहीं हुए और बैठक को स्थगित कर दिया गया। अब शनिवार सुबह 11 बजे दोबारा बैठक होगी। बैठक में केवल उपाध्यक्ष पद का चुनाव हो सका। पार्षद अनुराग मिश्रा ने चरनजीत गांधी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिस पर सर्वसम्मति से सहमति बनी और वह निर्विरोध चुनी गईं। चर्चा के दौरान सदस्य अरुण राय ने कहा कि सीवर सफाई व्यवस्था बेहद खराब है। जिस सुएज कंपनी को काम मिला है, उसने कई छोटे पेटी ठेकेदारों को यह जिम्मेदारी दे रखी है। चिनहट प्रथम वार्ड में जल निगम का ठेकेदार शैलेंद्र सफाई करा रहा है, जिससे काम की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। कई सदस्यों ने इसे अनुबंध का उल्लंघन बताते हुए नाराजगी जताई। महापौर ने इस पर जलकल जीएम और सचिव को जांच कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए।

लाइट मरम्मत व कर्मचारियों की कमी का मुद्दा

बैठक में मार्ग प्रकाश व्यवस्था भी प्रमुख मुद्दा रही। सदस्यों ने पूछा कि ईईएसएल को हटाने के बाद लाइटों की मरम्मत के इंतजाम क्यों नहीं किए गए। अपर नगर आयुक्त ललित कुमार ने बताया कि 100 कर्मचारी बढ़ाए गए हैं और बजट पास हो चुका है, लेकिन सदस्य संतुष्ट नहीं हुए और लिखित जवाब मांगा।

मृतक आश्रित की नियुक्ति में देरी

प्रचार विभाग के एक अनुचर की सड़क हादसे में मौत के आठ माह बाद भी उसकी पत्नी की नियुक्ति नहीं हो पाई। इस मामले को उठाते हुए सदस्यों ने अन्य लंबित मामलों की रिपोर्ट भी मांगी।

अब तीन महीने हो गए हैं, कुछ बोलिए बैठक के दौरान नगर आयुक्त ज्यादातर चुप्पी साधे रहे। महापौर सुषमा खर्कवाल ने टोका कि अब तीन महीने हो गए हैं, कुछ बोलिए। इसके बाद आयुक्त ने जवाब दिए, लेकिन सदस्य असंतुष्ट रहे। नतीजतन फैसला हुआ कि आगे चर्चा अब तभी होगी, जब अफसर लिखित जवाब देंगे।

अब यूपी में निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों पर ही मिलेगी सब्सिडी, ईवी पर 20 लाख तक मिलता है लाभ

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश में अक्तूबर महीने से अब यूपी में बनने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर ही सब्सिडी मिलेगी। ऐसी तैयारियां की जा रही हैं। इस बाबत प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा गया है। इस पर अभी अंतिम निर्णय होना है। ऐसा होने पर इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के लिए प्रदेश में यूनिटें लगाई जाएंगी। इससे रोजगार भी सृजित होगा। जबकि, अभी तक देश में कहीं भी निर्मित ईवी को यूपी में खरीदने पर सब्सिडी दी जा रही है। वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों की पॉलिसी लागू की गई। इसके तहत ईवी पर सब्सिडी देकर वाहनों की बिक्री को बढ़ावा दिया गया। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेशभर में बड़ी संख्या में वाहनों की खरीदारी हुई और ग्राहकों ने सब्सिडी का लाभ उठाया। करीब 60 करोड़ रुपये सब्सिडी के तहत दिए जा चुके हैं। इसी क्रम में अब पॉलिसी में बदलाव किया जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि 14 अक्तूबर से यह नया नियम लागू हो सकता है। चूंकि वर्ष 2022 में उपरोक्त तारीख से ही पॉलिसी लागू की गई थी, जिसके तीन वर्ष पूरे हो रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश में बनने वाले ईवी पर सब्सिडी देने से रोजगार सृजित होंगे। बड़ी–बड़ी कंपनियों को बिक्री बढ़ाने के लिए यूपी में यूनिटें लगानी होंगी। इससे रोजगार के साथ राजस्व की भी वृद्धि होगी। इससे प्रदेश की आर्थिक उन्नति होगी। अधिकारियों ने बताया कि 14 अक्तूबर, 2022 को ईवी पॉलिसी प्रदेश में लागू की गई थी। इसके तहत तीन साल तक ईवी खरीद पर शतप्रतिशत टैक्स व पंजीकरण में छूट दी जा रही है। इतना ही नहीं जिन्होंने टैक्स व पंजीकरण शुल्क भर दिया है, उन्हें रिफंड भी किया गया।

इतनी मिलती है सब्सिडी

5000 रुपये प्रति दो पहिया ईवी को

100000 रुपये प्रति चार पहिया ईवी को

2000000 रुपये प्रति ई बस को

100000 रुपये प्रति ई–गुड्स कैरियर को

17665 वाहनों को मिली 60 करोड़ रुपये सब्सिडी

17665 वाहन मालिकों ने सब्सिडी का लाभ उठाया

परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार ईवी सब्सिडी के रूप में अब तक 60 करोड़ रुपये बांटे जा चुके हैं। इस वर्ष अप्रैल से अब तक कुल 40 करोड़ रुपये सब्सिडी दी गई है। इतना ही नहीं आरटीओ स्तर से सब्सिडी देने की घोषणा के बाद सब्सिडी वितरण में तेजी आई है। अब तक 17665 वाहन मालिकों ने सब्सिडी का लाभ उठाया है, जबकि अभी भी 38285 आवेदन पेंडिंग हैं। परिवहन आयुक्त बीएन सिंह ने बताया कि प्रदेश में खरीदे जाने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी व टैक्स–पंजीकरण में छूट दी जा रही है। अक्तूबर में पॉलिसी के तीन साल पूरे हो जाएंगे। अब प्रदेश में बनने वाले ईवी पर सब्सिडी मिलेगी, इसे लेकर शासन को निर्णय लेना है।

ट्रेन में शराब पी रहे थे एसी मैकेनिक, आरपीएफ ने धरा

लखनऊ, (संवाददाता)। लखनऊ जंक्शन पर बरौनी मेल की पावरकार में शराब पी रहे एसी मैकेनिकों को आरपीएफ ने धर लिया। आरपीएफ एक्ट के तहत दोनों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन आरपीएफ प्रभारी अमित कुमार राय ने बताया कि शुक्रवार को उप निरीक्षक सीआईबी प्रशांत यादव के साथ स्टेशनका निरीक्षण कर रहे थे। गाड़ी संख्या 15204 लखनऊ जंक्शन बरौनी मेल प्लेटफॉर्म नंबर एक पर खड़ी थी। उन्होंने ट्रेन की जांच पड़ताल शुरू की। श्री राय ने बताया कि गाड़ी रवाना होने से आधे घंटे पूर्व पावरकार कोच(बिजली पैदा करने वाली बोगी) में दो

व्यक्तियों को अंदर बैठकर शराब पीते पाया गया। पूछताछ में दोनों ने अपने नाम दरभंगा निवासी मो. अलाउद्दीन एवं मुजफ्फरपुर निवासी प्रभात कुमार बताया। उन्होंने यह भी बताया कि वे प्राइवेट एसी मैकेनिक हैं। जो बरौनी मुख्यालय से संबंधित हैं। ट्रेन में एसी बोगियों की मेंटीनेंस देखते हैं। अमित कुमार राय ने यह भी बताया कि प्रभात कुमार के पास पुलिस वेरिफिकेशन की छायाप्रति थी, लेकिन मो. अलाउद्दीन के पास न ही कोई आईकार्ड और न ही पुलिस वेरिफिकेशन था। दोनों के पास से शराब के तीन टेट्रा पैक व बियर कैन बरामद किए गए हैं। बरौनी में संबंधित सीनियर सेक्शन इंजीनियर को मामले को लेकर सूचित कर दिया गया है। साथ ही आरपीएफ एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

जेपी नड्डा से मिले शाही, प्रदेश के लिए मांगी अतिरिक्त यूरिया मनमाने तरीके से हुई खरीद

लखनऊ, (संवाददाता)। प्रदेश के कई जिलों में खाद की मनमानी तरीके से खरीद होने का मामला सामने आया है। जैसे–जैसे जांच हो रही है, खाद खरीद की परतें खुलती जा रही हैं। विभिन्न जिलों में गई टीमें को यह शिकायत मिली है कि तमाम किसानों ने अपने खेत के रकबे में प्रयोग होने वाली मात्रा से दो से तीन गुना अधिक खाद खरीद ली है। वितरण प्रबंधन की इस चूक की वजह से खाद की किल्लत हुई है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की जांच में भी यह बात सामने आई थी कि महराजगंज में 186 लोगों ने एक से 2.37 मीट्रिक टन तक यूरिया खरीदा और सिद्धार्थनगर में भी कई किसानों ने 20 बार यूरिया की खरीद की। ऐसे में इन दोनों जिलों के साथ ही अन्य जिलों में भी निदेशालय से संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारियों को भेजा गया है। सूत्रों की मानें तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, चंदौली सहित अन्य जिलों में भी इस तरह

की शिकायतें मिल रही हैं। इसकी विस्तृत जांच चल रही है। अधिकारियों ने दर्ज मोबाइल नंबर पर कॉल करके माहभर के अंदर पांच बार खाद खरीदने वालों से पूछताछ की गई तो पता चला कि उन्होंने खाद खरीदी ही नहीं है। ऐसे में यह भी आशंका जताई जा रही है कि एक ही किसान के मोबाइल नंबर पर दूसरे व्यक्ति को खाद दिया गया है। इसी तरह कुछ किसानों ने धान की बुवाई एक से दो बीघे में की है, लेकिन यूरिया की खरीद तीन से चार बोरी किया है। जांच में लगे अधिकारी भी इसे कालाबाजारी से जोड़ कर देख रहे हैं।

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने शुक्रवार को केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात की। प्रदेश की स्थिति के बारे में जानकारी दी। किसानों की समस्या को देखते हुए यूरिया सहित अन्य खाद अतिरिक्त मात्रा में उपलब्ध कराने की मांग की। केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया है कि प्रदेश के किसानों को उनके द्वारा बोई गई फसल संस्तुति के अनुसार निरंतर खादों की आपूर्ति कराई जाएगी। कृषि मंत्री ने बताया कि एक से 20 अगस्त तक भारत सरकार द्वारा प्रदेश के लिए 204 रैक यूरिया भेजी गई है, जिसमें 190 रैक पहुंच गई है। 14 रैक तीन दिन में पहुंच जाएगी। इसके अलावा 21 अगस्त को यूरिया की 11 अतिरिक्त रैक रवाना की गई है। 22 अगस्त को 15 रैक रवाना हुई है, जो फिरोजाबाद, इटावा, बाराबंकी, गोंडा, एटा, बदायूं, अयोध्या, बस्ती, रामपुर, फतेहपुर, कानपुर, मैनपुरी, आजमगढ़, वाराणसी एवं मऊ जिले में तीन दिन में पहुंच जाएगी।

5.95 लाख मीट्रिक टन यूरिया मौजूद

कृषि विभाग के मुताबिक शुक्रवार को प्रदेश में कुल 5.95 लाख मीट्रिक टन यूरिया मौजूद है। 3.91 लाख मीट्रिक टन डीएपी और 3.01 लाख मीट्रिक टन एनपीके की उपलब्धता है। विभाग के मुताबिक प्रदेश में 266.50 रुपये से अधिक मूल्य पर यूरिया बेचने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। सीमावर्ती जिलों में कालाबाजारी और तस्करी रोकने के लिए चौकसी बढ़ा दी गई है।

संक्षिप्त खबरें

सरकार ने मुरादाबाद के कमिश्नर आन्जनेय सिंह को मूल कैडर के लिए किया रिलीव

लखनऊ, (संवाददाता)। यूपी सरकार ने मुरादाबाद के मंडलायुक्त आन्जनेय सिंह को उनके मूल सिक्किम कैडर के लिए रिलीव कर दिया है। नियुक्ति विभाग ने प्रतिनियुक्ति की समाप्ति पर नियमानुसार मिलने वाले 60 दिन का अवकाश भी उनके लिए स्वीकृत कर दिया है। बताते चलें कि आन्जनेय सिंह करीब 10 साल यूपी में प्रतिनियुक्ति पर रहे। वर्ष 2005 बैच के आईएएस अधिकारी आन्जनेय सिंह फरवरी 2015 में प्रतिनियुक्ति पर यूपी आए थे। वे यहां बुलंदशहर, फतेहपुर और रामपुर के डीएम रहे। 2 मार्च 21 से मुरादाबाद के कमिश्नर थे। नियुक्ति विभाग ने मुरादाबाद के कमिश्नर का चार्ज वहां के जिलाधिकारी को दे दिया है। शासन के सूत्रों के मुताबिक, अब यह केंद्र पर निर्भर करेगा कि उनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि बढ़ाता है या नहीं।

सहकारी बैंकों में क्यूआर कोड से भुगतान का शुभारंभ

लखनऊ, (संवाददाता)। राजधानी लखनऊ में शनिवार को सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने सहकारी बैंकों में क्यूआर कोड के जरिये भुगतान का शुभारंभ किया। कार्यक्रम महात्मा गांधी मार्ग स्थित यूपी को–आपरेटिव बैंक लिमिटेड में हुआ। इस मौके पर मंत्री ने किसानों को हो रही खाद समस्या से लेकर विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि किसान सहकारी समिति पर खाद ले रहे हैं। इस बार पहले से ज्यादा खाद बांटी गई है। मंत्री ने आगे कहा कि समितियों की मरम्मत भी कराई जा रही है। अब तक 980 सहकारी समिति की मरम्मत की गई। सपा शासनकाल में बंद समिति को चालू किया गया है। सभी को 10 लाख की मदद की गई है। हर जगह इंटरनेट की सुविधा दी जा रही है। बिजली के लिए हम लोग सोलर लाइट लगवा रहे हैं। सभी बंद समितियां खोली जा रही हैं। दूसरी जगह से भी मैन पवार का इंतजाम किया जा रहा है।

फर्जी आधार बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, बांग्लादेशी, रोहिंग्या नागरिकों का इस तरह बनता था अवैध कार्ड

लखनऊ, (संवाददाता)। बांग्लादेशी, रोहिंग्या नागरिकों का फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह के दो और सदस्यों सहारनपुर से बृहस्पतिवार देर रात गिरफ्तार किया है। इनमें बेहट निवासी अक्षय सैनी और थाना कोतवाली देहात निवासी तालिब अंसारी शामिल है। इस मामले में एटीएस अब तक 10 लोगों को दबोच चुकी है। वहीं जांच में सामने आया है कि इस गिरोह के तार यूपी, पश्चिम बंगाल, बिहार, दिल्ली, एनसीआर के साथ राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और हरियाणा तक फैले हैं। इस गिरोह का सरगना आजमगढ़ का मोहम्मद नसीम है, जिसे बाकी सात लोगों के साथ बृहस्पतिवार को गिरफ्तार किया गया था। एटीएस गिरोह के बाकी सदस्यों को तलाश रही है। एडीजी कानून–व्यवस्था अमिताभ यश ने बताया कि यह गिरोह इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल तरीके से बांग्लादेशी एवं रोहिंग्या घुसपैठियों के साथ विदेशी नागरिकों और अपात्रों के फर्जी आधार कार्ड समेत भारतीय नागरिकता के तमाम दस्तावेज बनाता है। गिरोह के सदस्य पंजीकृत जनसेवा केंद्रों में नौकरी करके सरकारी दस्तावेज बनाने की प्रक्रिया को समझते हैं और अधिकृत यूजर आईडी, पासवर्ड, थंब इंप्रेशन, आईरिश स्कैन अवैध रूप से हासिल करता है। वह अधिकृत लैपटॉप के मैक नंबर फाइंडिंग और जीपीएस को बाईपास कर फर्जी दस्तावेज बनाने का काम करते हैं। दलालों के माध्यम से ऐसे लोगों से संपर्क करते हैं, जिनके पास भारतीय नागरिकता का कोई दस्तावेज नहीं है। ऐसे लोगों के फर्जी दस्तावेज जैसे जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, शपथ पत्र आदि तैयार करने के बाद आधार कार्ड बनाता है। खासकर वर्ष 2023 के बाद 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों का सीधे आधार बनाने पर लगी रोक के मामले में वह फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर उनकी आयु कम दर्शा देता था और उनके आधार कार्ड जारी कर देता है। इसके लिए वह डमी यूजर भी बनाने के साथ सिस्टम आईडी का दुरुपयोग भी करते हैं।

पाकिस्तानी नागरिकों के बनाए फर्जी आधार

एटीएस की जांच में सामने आया है कि यह गिरोह द्वारा बनाए गए फर्जी आधार कार्ड के जरिये पासपोर्ट बनवाने वालों में बांग्लादेशी, रोहिंग्या, नेपाली नागरिकों के साथ पाकिस्तानी नागरिक भी शामिल हैं। फर्जी आधार कार्ड बनाने के लिए यह गिरोह 2 हजार रुपये से लेकर 40 हजार रुपये तक वसूलता था। फर्जी आधार के जरिये पासपोर्ट, अन्य सरकारी दस्तावेज और सरकारी योजनाओं का लाभ लिया जा रहा था। इस गिरोह के गिरफ्तार सदस्यों के पास से डीएम से लेकर लेखपाल तक के फर्जी स्टांप आदि बरामद किए गए हैं। एटीएस के इस खुलासे के बाद केंद्रीय खुफिया एजेंसियां और संबंधित राज्यों की पुलिस भी सतर्क हो गई है और तमाम जगहों पर लगातार छापे मारे जा रहे हैं।

रिकॉर्ड: एक दिन में 7047 ने डिजी यात्रा से की विमान यात्रा

लखनऊ, (संवाददाता)। डिजी यात्रा के जरिए विमानों में सफर करने वालों का नया रिकॉर्ड लखनऊ एयरपोर्ट पर बना है। बीती 18 अगस्त को 17 हजार यात्रियों ने एयरपोर्ट से सफर किया, जिसमें 7047 ने डिजी यात्रा का विकल्प चुना। यह 41 प्रतिशत है। यह एक दिन की सर्वाधिक संख्या है। डिजी यात्रा हवाई यात्रा को आसान और पेपरलेस बनाने की पहल है। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय पर 'डिजी यात्रा' के जरिए भी पैसेंजर सफर करते हैं। डिजी यात्रा का विकल्प चुनने वाले यात्रियों की यह संख्या घरेलू उड़ानों की है। अन्तरराष्ट्रीय फ्लाइटों के लिए डिजी यात्रा की सुविधा अभी नहीं है। एयरपोर्ट प्रशासन के मुताबिक मुख्य रूप से जिन यात्रियों को विमान में सवार होना होता है, उनके लिए डिजी यात्रा का विकल्प रहता है। सात हजार से अधिक मुसाफिरों ने डिजी यात्रा का विकल्प चुना। डिजी यात्रा सुविधा का उपयोग करने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट में प्रवेश करने के लिए न तो टिकट दिखाना पड़ता है, न ही अपनी पहचान के लिए आधार कार्ड या अन्य दस्तावेज दिखाने होते हैं। यह सेवा यात्रियों को एक अलग प्रवेश द्वार से एयरपोर्ट में प्रवेश की सुविधा देती है। इसके बाद यात्रियों का चेहरा ही उनकी पहचान बन जाता है। इस तकनीक से सुरक्षा जांच व बोर्डिंग प्रक्रिया तीव्र हो जाती है, जिससे पैसेंजरों का समय बचता है।

बढ़ रही यात्रियों की संख्या

लखनऊ एयरपोर्ट पर रनवे मरम्मत कार्य की वजह से दिन में रनवे बंद रहता था, लेकिन इस कार्य के पूरे होने के बाद पुरानी विमान सेवाओं को बहाल किया जा रहा है। हाल के दिनों में 12 फ्लाइटें बहाल हुई हैं। ऐसे में यात्रियों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है।

ग्रामीण पर्यटन की असली झलक दिखाने निकली फैम ट्रिप

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित ग्रामीण पर्यटन कॉन्क्लेव–2025 के सफल समापन के बाद आज प्रतिभागियों को गांव की असली खुशबू और परंपराओं से जोड़ने के लिए विशेष फैमिलियराइजेशन ट्रिप (फैम ट्रिप) का आयोजन किया गया। इस यात्रा का उद्देश्य प्रतिभागियों को ग्रामीण जीवन, परंपरागत व्यंजन, लोककला, संस्कृति और स्वयं सहायता समूहों के कार्यों से सीधे परिचित कराना रहा।ट्रिप के दौरान मेहमानों ने खेतों की पगडंडियों पर चलते हुए ग्रामीण परिवेश का अनुभव लिया और स्थानीय समुदाय की जीवनशैली को करीब से देखा। प्रतिभागियों में पीलीभीत, प्रयागराज, कन्नौज, फर्रुखाबाद, कानपुर, मथुरा, झांसी, जालौन, आगरा और लखीमपुर खीरी सहित विभिन्न जिलों से आए प्रतिनिधि शामिल रहे।पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि गांव केवल भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि भारत की ।

जिला मुख्यालयों की नगर पालिकाएं होंगी स्मार्ट और विकसित, मुख्यमंत्री योगी ने दी कार्ययोजना लागू करने की हरी झंडी

लखनऊ, (संवाददाता)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अपने सरकारी आवास पर नगर विकास विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए जिला मुख्यालयों की नगर पालिकाओं को स्मार्ट और विकसित नगर पालिका के रूप में रूपांतरित करने की योजना पर अमल शुरू करने के निर्देश दिए।मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य नगर पालिकाओं को आधुनिक, आत्मनिर्भर और नागरिक–केन्द्रित स्वरूप में विकसित करना है। अधिकारियों ने बताया कि योजना के तहत नगर पालिकाओं में गौरव पथ, पिंक टॉयलेट, शहरी सुविधा केंद्र, स्मार्ट क्लासरूम और आंगनबाड़ी, थीम आधारित पार्क, ऐतिहासिक धरोहर संरक्षण, जलाशयों का पुनर्जीवन, ईवी चार्जिंग स्टेशन, ग्रीन क्रेमेटोरियम और डिजिटल सेवाओं जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। साथ ही, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए उत्सव भवन, सामुदायिक केंद्र और 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' आधारित ढांचे भी स्थापित किए जाएंगे।मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि इस योजना को हब–एंड–स्पोक मॉडल पर लागू किया जा सकता है। इसके तहत लखनऊ और गोरखपुर के एकीकृत कमांड एवं कंट्रोल सेंटर से समीपवर्ती जिला मुख्यालयों की नगर पालिकाओं को जोड़ा जाएगा। इससे सुरक्षा, निगरानी और शिकायत निवारण जैसी सेवाओं में आधुनिकता आएगी और संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव होगा।उन्होंने कहा कि प्रत्येक नगर पालिका में परियोजनाओं का चयन स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर होना चाहिए तथा वित्तीय संसाधनों का आवंटन नगर निकायों की भौतिक और वित्तीय प्रगति के अनुरूप किया जाए। अधिकारियों ने जानकारी दी कि नगर निकायों को उनकी जनसंख्या और कार्यदक्षता के आधार पर 4 से 10 करोड़ रुपये तक का अनुदान देने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला मुख्यालयों की नगर पालिकाओं को स्मार्ट और विकसित स्वरूप देने से न केवल आधारभूत संरचना सुदृढ़ होगी बल्कि नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी सेवाएं भी मिलेंगी।

बैठक में लखनऊ और कानपुर में 200 इलेक्ट्रिक बसों को नेट कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मोड पर संचालित करने तथा अन्य नगरों में 650 बसों की प्रत्यक्ष खरीद का प्रस्ताव भी रखा गया। मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को प्रोत्साहित करने पर जोर देते हुए आवश्यक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए।उन्होंने सभी नगर निगमों में निवासियों के कर बकाये से जुड़ी विसंगतियों को दूर करने के लिए अभियान चलाकर आपत्तियां आमंत्रित करने और समाधान शिविर लगाकर नागरिकों की समस्याओं का संतोषजनक समाधान करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी नगर निकायों के पास अपना भवन होना चाहिए।बैठक में नगर निकायों की वित्तीय स्वीकृति सीमाओं को बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि बीते लगभग 20 वर्षों से इन सीमाओं में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 74वें संविधान संशोधन की भावना के अनुरूप नगर निकायों को अधिक वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार मिलने चाहिए। उन्होंने नगर आयुक्त, महापौर, कार्यकारिणी समिति और नगर निगम बोर्ड की वित्तीय स्वीकृति सीमाओं का तत्काल विस्तार करने का निर्देश दिया।मुख्यमंत्री ने लखनऊ में शहीद चंद्रशेखर आजाद अंतरराष्ट्रीय शूटिंग रेंज और बहुउद्देशीय खेल परिसर की स्थापना के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं को पीपीपी मोड पर प्राथमिकता के साथ शुरू किया जाए ताकि प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ें।

'जिलाधिकारी ने की इफको के आईआई एफडीसी के विक्रय प्रभारियों के साथ की बैठक'

'रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'हरदोई' शनिवार को विवेकानन्द सभागार में जिलाधिकारी अनुनय झा की अध्यक्षता में इफको के आईआई एफडीसी के विक्रय प्रभारियों की बैठक आहूत की गई। बैठक को सम्बोधित करते हुये जिलाधिकारी ने कहा कि केंद्रों के माध्यम से यूरिया उर्वरक वितरण कृषकों को सुगमता पूर्वक करना है। जनपद में कुल 52 इफको के केंद्र संचालित है जिनमें से 16 लोगों के पास दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। जिलाधिकारी ने सभी प्रतिष्ठानों को सीसीटीवी कैमरे लगवाने के निर्देश दिए। जिससे कैमरे की निगरानी में उर्वरक वितरण कराया जा सके, और यह

भी निर्णय लिया गया की सबसे पहले उन केंद्रों को उर्वरक उपलब्ध कराया जाएगा जिनके यहां सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। प्रभारी द्वारा सभी केंद्रों पर उर्वरक वितरण हेतु सीसीटीवी लगाए जाने के लिए आश्वस्त किया गया।

जिलाधिकारी ने जिला कृषि अधिकारी और क्षेत्रीय प्रबंधक इफको आकाश चौबे को निर्देशित किया कि सोमवार को प्राप्त होने वाली इफको के 2600 मेट्रिक टन यूरिया में से सबसे पहले सीसीटीवी वाले केंद्रों पर 15 मैट्रिक टन का प्रेषण किया जाए और उसके पश्चात मांग के अनुसार उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाएगा । उन्होंने सभी केंद्रों को स्टॉक रजिस्टर, वितरण रजिस्टर मेंटेन रखने के निर्देश दिए और यह भी निर्देश दिए गए की टोकन सिस्टम के द्वारा किसानों को यूरिया का वितरण उनके आधार कार्ड और खतौनी के आधार पर किया जाए एवं किसी भी प्रकार की टैगिंग और ओवर प्राइसिंग ना हो। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सान्या छाबड़ा, अपर जिलाधिकारी न्यायिक प्रफुल्ल त्रिपाठी ,सहायक आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता, अपर जिला सूचना अधिकारी दिव्या निगम द्वारा प्रतिभाग किया गया।

जनपद से टीबी का पूरी तरह से सफाया होने तक जारी रहेगा अभियान : सीएमओ

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर सिंगरामऊ स्थित सामाजिक संस्था ठाकुरबाड़ी महिला विकास कल्याण समिति के गौरीशंकर मंदिर सिंगरामऊ स्थित मुख्यालय पर शनिवार को 152 टीबी उपचाराधीनों को पोषाहार वितरित किया गया। इसमें अप्रैल माह में गोद लिए गए 68 मरीजों को छठीं बार तथा मई, जून, जुलाई के 84 मरीजों को पहली बार पोषाहार बांटा गया । बतौर मुख्य अतिथि सीएमओ डॉ लक्ष्मी सिंह ने कहा कि टीबी मुक्त भारत अभियान तब तक जारी रखेगा, जब तक कि जनपद से टीबी का पूरी तरह से सफाया नहीं हो जाता। अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग एक जनवरी से वल्नरेबल जनसंख्या में से उच्च जोखिम वाले टीबी मरीजों को खोजने के लिए व्यापक अभियान चला रहा है। सभी ब्लॉकों में हाई रिस्क पापुलेशन का चयन पूर्ण कर 31 जुलाई तक कुल 7008 टीबी रोगियों की खोज

कर ली गई है और इन सभी का उपचार किया जा रहा है। निःक्षय मित्रों के माध्यम से उन्हें पोषक सामाग्री दी जा रही है, ताकि वह शीघ्र स्वस्थ हो सकें। उन्होंने टीबी मरीजों को समय से पोषाहार उपलब्ध कराने के लिए ठाकुरबाड़ी महिला विकास कल्याण समिति की प्रमुख डॉ अंजू सिंह का प्रशंसा की। बोलीं कि ऐसे संगठनों से मिलने वाली पोषण सामाग्री की मदद से मरीजों के उपचार में सफलता की दर 95 प्रतिशत तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि दवाएं निरू शुल्क मिलतीं हैं। इसलिए इलाज एवं दवा के लिए पैसा मांगने पर उन्हें फोन करने की सलाह दी। अंत में लोगों की मांग पर उन्होंने टीबी हारेगा, देश जीतेगा, एक दिन गाकर टीबी मरीजों का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि टीबी से होने वाली मृत्यु दर पांच प्रतिशत से घटकर 2.6 प्रतिशत पर आ गई है। विशिष्ट अतिथि गांधी स्मारक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समोधपुर में मध्य एवं आधुनिक इतिहास विभाग में प्रोफेसर तथा वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में राज्यपाल निर्देशित गांव गोद कार्यक्रम के समन्वयक डॉ.राकेश कुमार यादव ने हर क्षेत्र में बढ़ती महिलाओं की भागीदारी का उल्लेख करते हुए ठाकुरबाड़ी संस्था तथा संस्था प्रमुख डॉ अंजू सिंह के प्रयासों की सराहना की। उन्हों ने विश्वविद्यालय की ओर से टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जनपद को टीबी मुक्त कराने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। संस्था प्रमुख डॉ अंजू सिंह ने बताया कि सरकार के इस कार्यक्रम में ठाकुरबाड़ी महिला विकास कल्याण समिति पूरी तरह से समर्पित है। उपचाराधीन सभी टीबी मरीज को लगातार छह माह तक पोषाहार देकर उन्हें शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने में मदद कर रही है। उन्होंने बताया कि टीबी उपचाराधीनों को जागरूक करने के साथ ही उनके परिवार की संस्था काउंसलिंग भी करती है।

बच्चों के कानूनी अधिकार व बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 पर विधिक जागरूकता शिविर

हरदोई(अम्बरीष कुमार सक्सेना)

आज राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ, के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई, के अध्यक्षध्जनपद न्यायाधीश संजीव शुक्ला सचिवध्अपर जिला जज भूपेंद्र प्रताप के निर्देशानुसार तहसील विधिक सेवा समिति सदर सचिवध्तहसीलदार सचिन्द्र कुमार शुक्ला के निर्देशन मे बच्चों के कानूनी अधिकार व बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन राजकीय इंटर कॉलेज हरदोई मे किया गया। जिसकी अध्यक्षता प्रधानाचार्य

श्याम नारायण यादव जी के द्वारा की गई जिनके द्वारा छात्रों को शिक्षा का महत्व एवं बच्चों के मौलिक अधिकार के बारे में जानकारी प्रदान की गई। शिविर में पी0एल0वी0 कीर्ति कश्यप के द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा चलाई जा रही निशुल्क विधिक सहायताओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि वह बच्चा जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो बालक की श्रेणी में आता है भारतीय संविधान के द्वारा बच्चों को कानूनी अधिकार प्रदान किए गए हैं जिसके अंतर्गत जीवन का अधिकार ,निशुल्क शिक्षा का अधिकार, बाल श्रम से सुरक्षा एवं शारीरिक शोषण या यौन शोषण के विरुद्ध अधिकारों के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान की और बच्चों से संबंधित कोई भी समस्या होने पर चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 का प्रयोग करने की सलाह प्रदान की शिविर में पीवएलवबीव शिवम कश्यप के द्वारा बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुए बताया गया कि जिन बच्चों की आयु 18 वर्ष से कम है अगर उनकी शादी करवाई जाती है तो यह कानूनन अपराध है जिसके लिए सजा का प्रावधान भी है।

शिक्षकों के चयन वेतन मान ऑफलाइन स्वीकृत किए जाएं- अक्षत पांडेय

हरदोई(अम्बरीष कुमार सक्सेना)

उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधिमण्डल संघ के प्रांतीय कोषाध्यक्ष शिव शंकर पांडेय की अध्यक्षता में संघ के जिलाध्यक्ष अक्षत पांडेय के नेतृत्व में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विजय प्रताप सिंह से उनके कार्यालय में मिल कर शिक्षकों की लंबित समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपा। प्रांतीय कोषाध्यक्ष शिव शंकर पांडेय ने कहा कि इससे पूर्व भी शिक्षक संघ द्वारा दिए गए ज्ञापनों में वर्णित समस्याओं का निस्तारण नहीं हो पाया, जिससे शिक्षकों में आक्रोश है। जिलाध्यक्ष श्री अक्षत पांडेय ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से माँग कि एक ही पद पर 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके शिक्षकों के चयन वेतनमान आफ लाइन आदेश निर्गत करें। परिषदीय विद्यालयों में नियुक्त ऐसे शिक्षकधशिक्षिकाएं जो पूर्व में

शिक्षामित्र के पद पर कार्यरत रहे हैं को पुरानी पेंशन हेतु विकल्प पत्र के संबंध में शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई कराई जाए। अन्य स्थानीय कर्मचारियों की उपलब्धता होने पर बीएलओ के रूप में शिक्षकों को अनावश्यक न लगाया जाए। ताकि छात्रों का पठन पाठन प्रभावित न हो। दिव्यांग शिक्षकों का दिव्यांग भत्ता शासनादेश के अनुसार 400/ के स्थान पर 1000 दिया जाए। जो भवन एवं कक्षा कक्ष जर्जर हैं उनके ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शीघ्र पूरी की जाए। जिन भवनों के ऊपर से हाईटेंशन लाइन निकली हुई है, शीघ्र हटवाने की कार्यवाही की जाए। जनपद के तमाम शिक्षकों का एक दिन का वेतन बाधित है और पत्रावलियाँ कार्यालय में लंबित हैं, शीघ्र निस्तारण किया जाए। कार्यालय द्वारा कुछ इंचार्ज प्रधानाध्यापकों को प्रधानाध्यापक का वेतन देने संबंधी आदेश जारी किया गया है, संघ ने माँग की कि जनपद के समस्त इंचार्ज प्रधानाध्यापकों को प्रधानाध्यापक का वेतन दिए जाने संबंधी आदेश जारी किया जाए। 31 मार्च 2025 को सेवा निवृत्त हो चुके शिक्षकों को 6 माह बीत जाने के बाद भी देयकों एवं पेंशन का भुगतान नहीं हो पा रहा है, शीघ्र भुगतान कराया जाए।एमडीएम हेतु कन्वर्जन कास्ट शीघ्र प्रेषित की जाए।शिक्षक मित्र व अनुदेशकों को भी समय से मानदेय दिया जाए। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने उ.प्र.प्रा. शिक्षक संघ के द्वारा सामने रखी गयी कई समस्याओं पर सम्बन्धित पटल सहायकों को बुलाकर हमेशा की तरह त्वरित समाधान भी कराया।

इस प्रतिनिधिमंडल में जिला मंत्री विपिन सिंह, कोषाध्यक्ष गजेंद्र प्रताप सिंह, अनंत राम पांडेय, हिमांशु श्रीवास्तव, अमित पांडेय, रूपेश अवस्थी, अनिल कुमार, अनुराग अवस्थी, क्षितिज मिश्रा, धर्मेंद्र कुमार, अतुल शुक्ला, निष्कर्ष चंदेल, नवीन चन्द्र मोहन, सुनील जी, संदीप पटेल, अनिल वर्मा, पंकज गौतम, अभिषेक प्रकाश शुक्ला, राम शरण मिश्रा, मोहित तिवारी, प्रशुभ सिंह, वैभव जैन आदि उपस्थित रहे।

निजी स्कूल के बच्चों को ले जा रही वैन पलटी

सीतापुर, (संवाददाता)। बच्चों को स्कूल से लेकर घर छोड़ने जा रही आरपी चिल्ड्रेन स्कूल की वैन शुक्रवार दोपहर बरगावां मार्ग पर खंती में पलट गई। हादसे के समय वैन में 10 विद्यार्थी सवार थे। चीख सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने वैन में फंसे बच्चों को किसी तरह बाहर निकाला। चालक लोगों की मदद से वैन को खंती से निकालकर मौके से भाग निकला। हादसे में तीन बच्चों को मामूली चोटें आईं हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कस्बे के एक निजी स्कूल में शुक्रवार दोपहर छुट्टी होने के बाद एक प्राइवेट वैन का चालक करीब 10 बच्चों को लेकर घर छोड़ने जा रहा था। चंद्रा गांव से आगे बरगावां मार्ग पर अचानक वैन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरी ।

संक्षिप्त खबरें

दो बार लिवर की जांच के बाद होगा हेपेटाइटिस का इलाज

सीतापुर, (संवाददाता)। बेहटा के सोनसरी गांव में हेपेटाइटिस के 141 मरीज मिलने के बाद उनका इलाज शुरू हो गया है। हेपेटाइटिस बी से पीड़ित 13 मरीजों को दवा देने से पहले दो बार उनके लिवर की जांच करवाई जाएगी। जांच में लिवर की स्थिति के आंकलन के आधार पर ही इलाज के लिए दवा दी जाएगी। पहले चरण में छह मरीजों ने जिला अस्पताल में एलएफटी (लिवर फंक्शन टेस्ट) की जांच करवाई है। गांव में 10 दिन पहले 78 मरीजों की केजीएमयू लखनऊ में हुई वायरल लोड की जांच रिपोर्ट में 35 मरीज हेपेटाइटिस सी व 13 मरीज हेपेटाइटिस बी से संक्रमित मिले थे। सी के मरीजों को सीएचसी बेहटा के माध्यम से दवाईयां देना शुरू करवा दिया गया है। चिकित्सकों को जिला अस्पताल में डॉ. स्वस्ति बाजपेयी ने ट्रेनिंग दी है। अब हेपेटाइटिस बी के 13 मरीजों के इलाज की प्रक्रिया शुरू की गई है। जिला अस्पताल में शुक्रवार को छह मरीज लिवर की जांच करवाने के लिए पहुंचे। डॉ. स्वस्ति बाजपेयी ने बताया कि इन मरीजों को दवा देने से पहले दो बार उनके लिवर की जांच करवाई जाएगी। पहली जांच के 15 दिन बाद दोबारा जांच होगी।

जिले में बनेगा पंचायत उत्सव भवन

सीतापुर, (संवाददाता)। ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत उत्सव भवन का निर्माण कराया जाएगा। इससे ग्रामीणों को मांगलिक कार्यक्रमों के लिए गेस्ट हाउस नहीं बुक कराना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्र की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पंचायत उत्सव भवन का निर्माण कराया जाना है। पहले चरण में जिले में एक पंचायत उत्सव भवन बनेगा। इस पर तकरीबन डेढ़ करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके लिए न्यूनतम तीन हजार वर्ग मीटर जमीन की जरूरत होगी। पंचायत उत्सव भवन में एक हॉल, स्टेज, मंडप सहित (100 लोगों की क्षमता का) तीन कमरे, जिसमें एक दिव्यांग हितैषी कमरा भूतल पर शौचालय सहित, रसोई घर आदि बनवाए जाएंगे। स्थल चयन के लिए डीएम की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। उपयुक्त जमीन की तलाश की जा रही है। इसके लिए जिला पंचायत राज अधिकारी डॉ. निरीश चंद्र साहू ने सभी एडीओ पंचायत से प्रस्ताव मांगे हैं।

आरबीएसबी इंटर कॉलेज का कुश्ती में जलवा

सीतापुर, (संवाददाता)। आरबीएसबी सिंह इंटर कॉलेज परिसर में शुक्रवार को जनपदीय माध्यमिक विद्यालयीय कुश्ती प्रतियोगिता 2025 का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता में जनपद के 20 विद्यालयों के 350 बालक व बालिकाओं ने अपना हुनर दिखाया। प्रतियोगिता में बालिका वर्ग में सर्वाधिक अंक व गोल्ड मेडल्स जीत कर आरबीएसबी सिंह इंटर कॉलेज कमलापुर चौंपियन बना। बालिका वर्ग में द्वितीय स्थान प्राप्त करके किसान इंटर कॉलेज सरैया राजा साहब ने उपविजेता का खिताब जीता। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटर कॉलेज गोड़ैचा ने बालक वर्ग का जनपदीय उपविजेता का खिताब जीता। आरबीएसबी सिंह इंटर कॉलेज ने जनपद का ओवरऑल चौंपियनशिप का खिताब भी जीता। इस दौरान प्रधानाचार्य साकिब जमाल अंसारी, जनपदीय क्रीड़ा सचिव अवधेश नंदन पांडेय, आरबीएसबी सिंह इंटर कॉलेज के शारीरिक शिक्षा शिक्षक अनूप सिंह, धीरेंद्र कश्यप व अन्य उपस्थित रहे।

टेढ़ी बाजार पुल से मोहबरा बाईपास तक फैंसी लाइटों के न जलने से शाम होते ही हो जाता है अंधेरा

अयोध्या।टेढ़ी बाजार पुल से होते हुए मोहबरा चौराहा बाईपास तक लोक निर्माण विभाग द्वारा सौंदर्यीकरण के लिए लगाई गई फैंसी लाइटे एक वर्ष से महज शो पीस बनी हुई है।जबकि इस मार्ग से ही राम मंदिर परिसर आने वाले श्रद्धालुओं की भारी संख्या में आवाजाही लगी रहती है।क्योंकि इस पुल के ऊपर से ही होकर लखनऊ गोरखपुर हाईवे को जाने के लिए सुगम एवं सरल रास्ता है।जिसके चलते इधर से देर रात तक श्रद्धालुओं की आवाजाही लगा रहता है।लेकिन शाम होते ही इन फैंसी लाइटों के ना जलने के चलते किसी भी दुर्घटना व किसी अनहोनी घटना को लेकर श्रद्धालुओं के साथ–साथ अन्य लोगों में भय बना रहता है।बताते चलें कि इस पुल से बाईपास तक की दूरी लगभग 1.320 किलो मीटर है।इस मार्ग की सौंदर्यीकरण के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्ग के बीच में कुल 60 पोल लगे हुए हैं।इसके अलावा इस मार्ग के दोनों तरफ 60–60 पोल कुल मिलाकर 120 पोल लगे हैं।जिसमें लगभग 180 फैंसी लाइटे लगी हुई है। परंतु यह लाइटे 1 वर्ष पूर्व तो लग चुकी है लेकिन अभी तक नहीं जली जो महज शो पीस बनी हुई है।शाम होते ही यहां पर अंधेरा छा जाता है।जिसके चलते जहां एक ओर आए दिन दुर्घटना होती रहती है वही लूट, छिनैती सहित अन्य किसी अनहोनी घटना को लेकर लोग चिंतित भी रहते हैं।सूत्रों के मुताबिक लोक निर्माण विभाग की ओर से पूरी तरीके से पोल लग गया है इन पोलों में फैंसी लाइट भी लगी है।लोक निर्माण विभाग की ओर से कोई कमी नहीं है।लेकिन विद्युत वितरण खंड प्रथम के लापरवाही के चलते यह लाइट नहीं जल पा रही है।इन पोलो में अंदर से पाइप डालकर सिर्फ कनेक्शन देना है।जो कि बिजली विभाग का काम है।लोक निर्माण विभाग द्वारा कई बार पत्राचार किया गया लेकिन अभी तक स्थिति जस की तस बनी हुई है।उम्मीद यही जताई जा रही है कि इस दीपोत्सव के पहले पहले यह लाइटें जलने लगेगी।

नौ ईंट भट्ठा संचालकों से 22.25 लाख की वसूली

भदोही, (संवाददाता)। तहसीलदार ज्ञानपुर अजय सिंह के नेतृत्व में शुक्रवार को व्यापार कर विभाग की टीम ने टैक्स चोरी करने वाले ईंट भट्ठा संचालकों पर बड़ी कार्रवाई की। नौ ईंट–भट्ठा संचालकों के यहां व्यापार कर की चोरी पकड़े जाने पर विभागीय स्तर से 22.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। इस कार्रवाई से टैक्स की चोरी करने वाले ईंट भट्ठा संचालकों में खलबली मच गई। उद्योग धंधा संचालित करने वाले लोगों को शासन से निर्धारित टैक्स को समय–समय पर जमा करना पड़ता है। इसी में व्यापार कर भी शामिल है। कुछ ईंट भट्ठा संचालकों की तरफ से टैक्स की चोरी की जाती है। कई बार नोटिस जारी करने के बाद भी टैक्स न जमा करने पर आरसी जारी की जाती है। शुक्रवार को तहसीलदार ज्ञानपुर अजय सिंह के नेतृत्व में व्यापार कर विभाग की टीम ने ज्ञानपुर तहसील क्षेत्र में वसूली अभियान चलाया। इस दौरान श्रद्धा ईंट उद्योग, अंश ईंट उद्योग, सतनाम ईंट उद्योग, सनी कंस्ट्रक्शन, शक्ति ईंट उद्योग, पीएनएस ईंट उद्योग, रोहित ईंट उद्योग, एसकेएस ईंट उद्योग, बीबीएस ईंट की जांच की गई। अभियान के दौरान कर से जुड़ी अनियमितता मिलने पर कुल 22.25 लाख रुपये का चालान किया गया।

एसडीएम की अध्यक्षता में हुआ थाना समाधान दिवस का आयोजन'

'रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'पाली–(हरदोई)' शनिवार को पाली थाना परिसर में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता तहसील सवायजपुर के उपजिलाधिकारी मयंक कुण्डू ने की, जबकि संयोजन थाना प्रभारी सोमपाल गंगवार ने किया। थाना समाधान दिवस में कुल 10 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। सभी शिकायतें राजस्व से संबंधित थीं। मौके पर किसी भी शिकायत का निस्तारण नहीं हो सका। सभी शिकायती पत्रों को संबंधित हल्का लेखपालों को सौंप दिया गया। शिकायतों के लिए राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम गठित कर एसडीएम ने उक्त सभी शिकायतों का एक सप्ताह के अंदर निस्तारण करने के निर्देश दिए। उपजिलाधिकारी मयंक कुण्डू ने संबंधित राजस्व अधिकारीध्कर्मचारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण और ससमय हो और मौके पर जाकर किया जाए। उन्होंने कहा कि इससे एक ही शिकायत बार–बार नहीं आएगी और राजस्व तथा पुलिस का समय बचेगा। उन्होंने एक ही बार में गुणवत्तापूर्ण शिकायत निस्तारण पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि आवास

से संबंधित किसी की भी समस्या हो अर्थात पात्र व्यक्ति को आवास मिलने में कठिनाई आ रही हो या पात्र व्यक्ति को आवासीय योजना से वंचित किया जा रहा हो तो इसकी सूचना मुझे तत्काल दी जाए जिससे पात्र व्यक्ति को सरकार की आवासीय योजना से लाभान्वित कर न्याय दिलाया जा सके। उन्होंने नगर में फैले अतिक्रमण हटाने को लेकर संबंधित नगर पंचायत कर्मियों से कहा कि सर्वप्रथम अतिक्रमण कारियों को निर्धारित समय में अतिक्रमण हटाने का नोटिस भेजा जाए। अन्यथा की स्थिति में राजस्व ,नगर पंचायत एवं पुलिस की संयुक्त टीम गठित कर युद्ध स्तर पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। कार्यक्रम में राजस्व विभाग से कानूनगो विजय मौर्या, लेखपाल अभिषेक द्विवेदी, गौरव यादव,फुरखान, नीरज अग्निहोत्री, विनोद दीक्षित, प्रमोद,मंजू राठौर, चकबंदी लेखपाल अंकित,आनन्द के अतिरिक्त उपनिरीक्षक अनिल कुमार दुबे,उपनिरीक्षक उमेश तिवारी, हेड मुंशीध्दीवान योगेंद्र कुमार यादव आदि उपस्थित रहे।

आंतरिक रिहर्सल कर दीक्षांत की तैयारियों को परखा

गोरखपुर, (संवाददाता)। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में 25 अगस्त को आयोजित दीक्षांत समारोह की तैयारियों को परखने के लिए शुक्रवार को आंतरिक रिहर्सल का आयोजन किया गया। महायोगी गुरु श्रीगोरक्षनाथ शोधपीठ में आयोजित रिहर्सल में सभी समितियों के पदाधिकारियों और पदक विजेताओं ने प्रतिभाग किया। पूर्वाभ्यास के दौरान कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल की भूमिका प्रो. सुधा यादव ने निभाई। मुख्य अतिथि पद्मश्री प्रो. आशुतोष शर्मा की भूमिका डॉ. कुशल नाथ मिश्र, विशिष्ट अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र यादव की भूमिका डॉ. आमोद राय व विशिष्ट अतिथि उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी की भूमिका प्रो. उषा सिंह ने निभाई। दीक्षांत में पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने वाले शोधार्थियों ने भी प्रतिभाग किया। इसमें विश्वविद्यालय की तरफ से गोद लिए गए गांवों के वे विद्यार्थी भी शमिल हुए जिन्हें दीक्षांत समारोह के मंच से कुलाधिपति के हाथों पुरस्कृत किया जाएगा। संचालन डॉ. तूलिका मिश्रा ने किया। इस दौरान प्रति कुलपति प्रो. शांतनु रस्तोगी, प्रो. नंदिता सिंह आदि मौजूद रहीं।

पांचवीं का छात्र कृष्ण देगा मंच से भाषण

राजभवन की पहल पर पहली बार स्कूली बच्चे को दीक्षांत के मंच से भाषण देने का मौका मिलेगा। तीन चरणों की कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद पिपराइच क्षेत्र के मुड़ियारी खुर्द स्थित प्राथमिक विद्यालय के पांचवीं के छात्र कृष्ण को यह मौका मिलेगा। एनएसएस के समन्वयक डॉ. सत्यपाल सिंह ने बताया कि विजेता के रूप में कृष्ण मेरा देश विषय पर तीन मिनट का भाषण देगा। डीडीयू में दीक्षोत्सव के तहत आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को शुक्रवार को पुरस्कृत किया गया। कुलपति प्रो. पूनम टंडन ने उन्हें प्रमाणपत्र प्रदान कर सम्मानित किया। इस मौके पर कुलपति ने कहा कि प्रतियोगिताएं केवल पुरस्कार प्राप्ति तक सीमित नहीं होतीं बल्कि ये छात्रों के व्यक्तित्व निर्माण, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और टीम भावना को सुदृढ़ करने में सहायक होती हैं। प्रति कुलपति प्रो. शांतनु रस्तोगी ने भी संबोधित किया।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबंधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।